महोदय, आज इस डिजिटल युग में केंद्र की मोदी जी की सरकार हम सबकी डिजिटल सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए सराहनीय काम भी कर रही है। इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई-नई तकनीकी का विकास हो रहा है, जिसमें डीपफेक भी एक तकनीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके किसी व्यक्ति के चेहरे, आवाज या हाव-भाव को बदल देती है। महोदय, डीपफेक का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या बन गई है, क्योंकि इस तकनीक के नकारात्मक इस्तेमाल से न केवल व्यक्तिगत गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है, बल्कि इससे समाज में और भी कई गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

महोदय, डीपफेक का मतलब है, एक व्यक्ति के चेहरे, आवाज या शरीर को किसी दूसरे व्यक्ति पर नकली तरीके से लगाना। यह तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके वीडियो और ऑडियो को इतना सटीक बना देती है कि असली और नकली में अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। महोदय, डीपफेक के नकारात्मक इस्तेमाल से कई सवाल उठते हैं, जैसे, निजता की सुरक्षा, पारदर्शिता और निष्पक्षता। आजकल इंटरनेट और वैश्विक प्लेटफॉर्म की तेजी से बढ़ती तकनीक के कारण डीपफेक के नकारात्मक प्रभाव को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूँ कि डीपफेक तकनीक का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि सभी नागरिक सुरक्षित महसूस कर सकें, धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Shrimati Darshana Singh:- Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Subhash Barala (Haryana), Shri Ram Chander Jangra (Haryana), Ms. Indu Bala Goswami (Himachal Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shrimati S. Phangnon Konyak (Nagaland), Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade (Maharashtra), Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Dr. Parmar Jashvantsinh Salamsinh (Gujarat), Shrimati Maya Naroliya (Madhya Pradesh), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri Sujeet Kumar (Odisha).

Concern over the problems faced by potato farmers in the country

श्री रामजी लाल सुमन (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, पूरे देश में आलू किसानों की हालत बहुत खराब है। 2014 में जब श्री नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार थे, तो आगरा की जनसभा में उन्होंने आलू किसानों को आश्वस्त किया था कि जिस तरह गुजरात के बनासकांठा में

हमने आलू प्रसंस्करण की इकाई स्थापित की है, उसी तर्ज पर सरकार में आने के बाद हम आलू प्रसंस्करण की इकाई स्थापित करेंगे।

उपसभाध्यक्ष जी, आलू की लागत 1,600 रुपए प्रति क्विंटल आती है और पिछली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो खरीद घोषित की, वह 459 रुपए प्रति क्विंटल की थी। इससे ज्यादा मजाक और दूसरा कोई हो नहीं सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आलू को उद्यान में शामिल किया जाता है, जिसको हटाकर कृषि में शामिल किया जाए। उपसभाध्यक्ष जी, चीन में आलू बोर्ड है और चीन यह पहले से समझ लेता है कि कितने एकड़ में आलू की बुआई हुई है, तो देश में कितना उत्पादन होगा, कितनी खपत होगी और कितना आलू खराब होगा, यह पता चल जाता है। वहां सड़े आलू का भी इस्तेमाल होता है और वह सड़ा-गला आलू, आलू प्रसंस्करण में चला जाता है। महोदय, यह भी बहुत जरूरी है कि इसी तरह का बोर्ड हमारे देश में भी बनना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके मार्फत यह बताना चाहूँगा कि किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज नहीं मिलता। हमारे देश में अनुसंधान की जो व्यवस्था होनी चाहिए, वह अनुसंधान की व्यवस्था नहीं है। आलू उत्पादन में हिंदुस्तान का तीसरा स्थान है। मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहूँगा कि आलू किसान आलू का जो उत्पादन करता है, उसमें किसान केवल 65 प्रतिशत ही अपनी फसल का मूल्य ले पाता है।

हमारे देश में 35 फीसदी आलू सड़ जाता है। इसलिए मेरा भारत सरकार से यह अनुरोध है कि आलू को बागवानी से हटाकर खाद्य में शामिल किया जाए, कृषि में शामिल किया जाए। हमारे देश में उच्च गुणवत्ता का बीज उपलब्ध हो, जिससे निर्यात हो सके। आलू अनुसंधान केंद्र खोले जाएं और चीन की तरह हमारे देश में भी आलू बोर्ड बनाया जाए तथा आलू प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाए, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Ramji Lal Suman: Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh), Shri A. A. Rahim (Kerala), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Haris Beeran (Kerala) and Dr. Fauzia Khan (Maharashtra).

Demand to include the Musi River in Hyderabad as part of the country's major river rejuvenation project

SHRI ANIL KUMAR YADAV MANDADI (Telangana): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for allowing me to speak on demand to include the Musi River in Hyderabad, Telangana under the Central Government Scheme for Rejuvenation of Major Rivers in the Country.